



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 2 जनवरी, 2026

पौष 12, 1947 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या266/79-वि-1-2026-1-क-27-2025

लखनऊ, 2 जनवरी, 2026

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश विनियोग (2025-2026 का अनुपूरक) विधेयक, 2025जिससे वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 2जनवरी, 2026 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2026 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश विनियोग (2025-2026 का अनुपूरक) अधिनियम, 2025

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2026)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

31 मार्च, 2026को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (2025-2026 का अनुपूरक) संक्षिप्त नाम अधिनियम, 2025 कहलायेगा।

2-ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 2026 ई० को समाप्त होने वाले उत्तर प्रदेश राज्य की वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, समेकित निधि में से वर्ष उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा 2025-2026 के लिए सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल 24496,97,72,000रुपये योग24496,97,72,000 रुपये (रुपये चौबीस हजार चार सौ छियानवे करोड़ सत्तावने लाख का दिया जाना बहत्तर हजार मात्र) होता है,से अधिक न हो।

विनियोग

3-इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का प्राधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची
(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2	3			
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)			
क्रम संख्या		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग	
01	आबकारी विभाग	पूंजी :	2625.00	--	2625.00
03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व :	300.00	--	300.00
04	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	पूंजी :	150.00	--	150.00
06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व :	8501.00	--	8501.00
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व :	169316.42	--	169316.42
		पूंजी :	318105.00	--	318105.00
08	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री)	राजस्व :	100.00	--	100.00
09	ऊर्जा विभाग	राजस्व :	374445.00	--	374445.00
		पूंजी :	77665.00	--	77665.00
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	राजस्व :	2666.34	--	2666.34
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व :	7764.45	--	7764.45
		पूंजी :	2695.00	--	2695.00
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व :	20000.00	--	20000.00
		पूंजी :	2551.00	--	2551.00
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व :	1495.50	--	1495.50
		पूंजी :	532.15	--	532.15
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व :	2650.00	--	2650.00
		पूंजी :	1100.00	--	1100.00

अनुसूची

--(क्रमशः):

1	2	3			
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)			
क्रम संख्या		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग	
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व :	515.71	--	515.71
		पूंजी :	2000.00	--	2000.00
19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	पूंजी :	2558.00	--	2558.00
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व :	--	8000.00	8000.00
21	खाद्य तथा रसद विभाग	पूंजी :	1347.00	--	1347.00
22	खेल विभाग	पूंजी :	1.00	--	1.00
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	पूंजी :	40000.00	--	40000.00
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व :	40718.30	--	40718.30
		पूंजी :	46.00	--	46.00
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	30000.00	--	30000.00
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व :	196505.00	--	196505.00
37	नगर विकास विभाग	राजस्व :	109648.00	--	109648.00
		पूंजी :	64000.00	--	64000.00
40	नियोजन विभाग	राजस्व :	5017.40	--	5017.40
		पूंजी :	121.00	--	121.00
42	न्याय विभाग	राजस्व :	13000.00	--	13000.00
43	परिवहन विभाग	राजस्व :	5000.00	--	5000.00
		पूंजी :	1.00	--	1.00
44	पर्यटन विभाग	राजस्व :	110.00	--	110.00
		पूंजी :	1002.00	--	1002.00
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व :	446.30	--	446.30
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व :	46.95	--	46.95

अनुसूची				
--(क्रमशः):				
1	2	3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		(लाख रुपयों में)		
क्रम संख्या		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व : 450.00	--	450.00
		पूंजी : 63445.70	--	63445.70
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व : 53500.00	--	53500.00
		पूंजी : 700.00	--	700.00
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व : 1050.00	--	1050.00
		पूंजी : 500.00	--	500.00
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	राजस्व : 125.03	--	125.03
		पूंजी : 2.00	--	2.00
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व : 674.47	--	674.47
55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	पूंजी : 2000.00	337.05	2337.05
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	राजस्व : 1.00	--	1.00
		पूंजी : 1000.00	--	1000.00
60	वन विभाग	राजस्व : 350.00	--	350.00
		पूंजी : 9000.00	--	9000.00
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व : 30.00	500000.11	500030.11
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)	राजस्व : 448.00	--	448.00
		पूंजी : 309.93	--	309.93
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व : 1244.10	7.00	1251.10
		पूंजी : 4015.20	--	4015.20
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व : 2331.21	--	2331.21
		पूंजी : 450.00	--	450.00

अनुसूची					
--(क्रमशः):					
1	2	3			
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक			
		(लाख रूपयों में)			
क्रम		विधान सभा द्वारा	राज्य की समेकित निधि पर	योग	
संख्या		स्वीकृत	भारित		
69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	15000.00	--	15000.00
		पूंजी :	3900.00	--	3900.00
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व :	50000.00	--	50000.00
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व :	1590.14	--	1590.14
75	शिक्षा विभाग(राज्य शैक्षिक	पूंजी :	101.00	--	101.00
	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)				
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	पूंजी :	2615.63	--	2615.63
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व :	400.00	--	400.00
79	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन	राजस्व :	40463.63	--	40463.63
	सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग				
	कल्याण)	पूंजी :	1343.47	--	1343.47
80	समाज कल्याण विभाग(समाज	राजस्व :	20558.75	--	20558.75
	कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का				
	कल्याण)				
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति	राजस्व :	4257.19	--	4257.19
	कल्याण)	पूंजी :	100.00	--	100.00
83	समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित	राजस्व :	143578.67	--	143578.67
	जातियों के लिये विशेष घटक				
	योजना)	पूंजी :	6100.00	--	6100.00
86	सूचना विभाग	राजस्व :	3976.00	--	3976.00
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व :	50.00	--	50.00
92	संस्कृति विभाग	राजस्व :	500.00	--	500.00
		पूंजी :	347.92	--	347.92

अनुसूची

(समाप्त):

1	2	3			
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)			
क्रम संख्या		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकत निधि पर भारित	योग	
93	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग	राजस्व :	98.00	--	98.00
95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	पूंजी :	1.00	--	1.00
	योग :	राजस्व :	1328922.56	508007.11	1836929.67
		पूंजी :	612431.00	337.05	612768.05
	महायोग :		1941353.56	508344.16	2449697.72

उद्देश्य और कारण

संविधान के अनुच्छेद 204 के साथ पठित अनुच्छेद 205 के अधीन विधान सभा द्वारा अनुपूरक अनुदानों की मांगें स्वीकृत किये जाने के बाद, राज्य विधान मण्डल में एक विनियोग विधेयक पुरःस्थापित करना आवश्यक है।

यह विधेयक इस बात की व्यवस्था करता है कि वित्तीय वर्ष 2025-2026 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुपूरक अनुदानों तथा राज्य की समेकित निधि पर भारित अनुपूरक व्ययों के लिये जो धन अपेक्षित है, उसका विनियोग उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से हो सके।

तदनुसार उत्तर प्रदेश विनियोग (2025-2026 का अनुपूरक) विधेयक, 2025 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
जे० पी० सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

No. 266(2)/LXXIX-V-1-2026-1-ka-27-2025

Dated Lucknow, January 2, 2026

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Viniyog (2025-2026 ka Anupurak) Adhiniyam, 2025(Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 1 of 2026) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on January 2, 2026. The Vitt (Aay-Vyayak) Anubhag-2 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH APPROPRIATION
(SUPPLEMENTARY 2025-2026) ACT, 2025

(U.P. Act no. 1 of 2026)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to provide for authorising payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State to the services for the year ending on thirty-first day of March, 2026.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Appropriation Short title
(Supplementary 2025-2026) Act, 2025.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in Column-3 of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Rs 24496,97,72,000 (Rs. twenty four thousand four hundred ninety six crore ninety seven lac seventy two thousand only) towards defraying the several charges which will come in course of payment during the year ending on the thirty-first day of March, 2026 in respect of the services and purposes specified in Column-2 of the Schedule.

Issue of
Rs.24496,97,72,000
out of the
Consolidated Fund
of the State of
Uttar Pradesh for the
Year 2025-2026

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the year ending on the thirty-first day of March, 2026.

Appropriation

SCHEDULE

(See Section 2 and 3)

1	2	3		
Grant/Serial	Services and purposes	Sums not exceeding		
		(In lakhs)		
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated fund of the State	Total
01	Excise Department	Capital : 2625.00	--	2625.00
03	Industries Department (Small Industry and Export Promotion)	Revenue : 300.00	--	300.00
04	Industries Department (Mines and Minerals)	Capital : 150.00	--	150.00
06	Industries Department (Handloom Industry)	Revenue : 8501.00	--	8501.00
07	Industries Department (Heavy and Medium Industries)	Revenue : 169316.42	--	169316.42
		Capital : 318105.00	--	318105.00
08	Industries Department (Printing and Stationery)	Revenue : 100.00	--	100.00
09	Power Department	Revenue : 374445.00	--	374445.00
		Capital : 77665.00	--	77665.00
10	Agriculture and Other Allied Departments (Horticulture & Sericulture Development)	Revenue : 2666.34	--	2666.34
11	Agriculture and Other Allied Departments (Agriculture)	Revenue : 7764.45	--	7764.45
		Capital : 2695.00	--	2695.00
14	Agriculture and Other Allied Departments (Panchayati Raj)	Revenue : 20000.00	--	20000.00
		Capital : 2551.00	--	2551.00
15	Agriculture and Other Allied Departments	Revenue : 1495.50	--	1495.50

SCHEDULE

--(Contd):

1	2	3			
Grant/Serial	Services and purposes	Sums not exceeding			
		(In lakhs)			
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated fund of the State	Total	
(Animal Husbandry)					
	Capital :	532.15	--	532.15	
16	Agriculture and Other Allied Departments (Dairy Development)	Revenue :	2650.00	--	2650.00
	Capital :	1100.00	--	1100.00	
18	Agriculture and Other Allied Departments (Cooperative)	Revenue :	515.71	--	515.71
	Capital :	2000.00	--	2000.00	
19	Personnel Department (Training and Other Expenditure)	Capital :	2558.00	--	2558.00
20	Personnel Department(Public Service Commission)	Revenue :	--	8000.00	8000.00
21	Food and Civil Supplies Department	Capital :	1347.00	--	1347.00
22	Sports Department	Capital :	1.00	--	1.00
24	Cane Development Department (Sugar Industry)	Capital :	40000.00	--	40000.00
31	Medical Department (Medical Education and Training)	Revenue :	40718.30	--	40718.30
	Capital :	46.00	--	46.00	
32	Medical Department (Allopathy)	Revenue :	30000.00	--	30000.00
35	Medical Department (Family Welfare)	Revenue :	196505.00	--	196505.00

SCHEDULE

--(Contd):

1	2	3			
Grant/Serial	Services and purposes	Sums not exceeding			
		(In lakhs)			
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated fund of the State	Total	
37	Urban Development Department	Rcvnue :	109648.00	--	109648.00
		Capital :	64000.00	--	64000.00
40	Planning Department	Revenue :	5017.40	--	5017.40
		Capital :	121.00	--	121.00
42	Judicial Department	Revenue :	13000.00	--	13000.00
43	Transport Department	Revenue :	5000.00	--	5000.00
		Capital :	1.00	--	1.00
44	Tourism Department	Revenue :	110.00	--	110.00
		Capital :	1002.00	--	1002.00
45	Environment Department	Revenue :	446.30	--	446.30
46	Administrative Reforms Department	Revenue :	46.95	--	46.95
47	Technical Education Department	Revenue :	450.00	--	450.00
		Capital :	63445.70	--	63445.70
49	Women & Child Welfare Department	Revenue :	53500.00	--	53500.00
		Capital :	700.00	--	700.00
50	Revenue Department (District Administration)	Revenue :	1050.00	--	1050.00
		Capital :	500.00	--	500.00
51	Revenue Department (Relief on Account of Revenue :		125.03	--	125.03

SCHEDULE

--(Contd):

1	2	3			
Grant/Serial	Services and purposes	Sums not exceeding			
		(In lakhs)			
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated fund of the State	Total	
Natural Calamities)					
	Capital :	2.00	--	2.00	
52	Revenue Department (Board of Revenue and other expenditure)	Revenue :	674.47	--	674.47
55	Public Works Department (Buildings)	Capital :	2000.00	337.05	2337.05
58	Public Works Department (Communications-Roads)	Revenue :	1.00	--	1.00
	Capital :	1000.00	--	1000.00	
60	Forest Department	Revenue :	350.00	--	350.00
	Capital :	9000.00	--	9000.00	
61	Finance Department (Debt Services and Other Expenditure)	Revenue :	30.00	500000.11	500030.11
65	Finance Department (Audit, Small Savings etc.)	Revenue :	448.00	--	448.00
	Capital :	309.93	--	309.93	
67	Legislative Council Secretariat	Revenue :	1244.10	7.00	1251.10
	Capital :	4015.20	--	4015.20	
68	Legislative Assembly Secretariat	Revenue :	2331.21	--	2331.21
	Capital :	450.00	--	450.00	
69	Vocational Education Department	Revenue :	15000.00	--	15000.00

SCHEDULE

(Contd.):

1	2	3			
Grant/Serial	Services and purposes	Sums not exceeding			
		(In lakhs)			
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated fund of the State	Total	
	Capital :	3900.00	--	3900.00	
70	Science and Technology Department	Revenue :	50000.00	--	50000.00
72	Education Department (Secondary Education)	Revenue :	1590.14	--	1590.14
75	Education Department (State Council of Education Research & Training)	Capital :	101.00	--	101.00
76	Labour Department (Labour Welfare)	Capital :	2615.63	--	2615.63
78	Secretariat Administration Department	Revenue :	400.00	--	400.00
79	Social Welfare Department (Empowerment Of The Handicapped & Welfare Of Backward Classes)	Revenue :	40463.63	--	40463.63
	Capital :	1343.47	--	1343.47	
80	Social Welfare Department (Social Welfare & Welfare of Scheduled Castes)	Revenue :	20558.75	--	20558.75
81	Social Welfare Department (Tribal Welfare)	Revenue :	4257.19	--	4257.19
	Capital :	100.00	--	100.00	
83	Social Welfare Department (Special Component Plan for Scheduled Castes)	Revenue :	143578.67	--	143578.67
	Capital :	6100.00	--	6100.00	
86	Information Department	Revenue :	3976.00	--	3976.00
87	Soldier's Welfare Department	Revenue :	50.00	--	50.00

SCHEDULE					
(Contld):					
1	2	3			
Grant/Serial	Services and purposes	Sums not exceeding			
		(In lakhs)			
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated fund of the State	Total	
92	Culture Department	Revenue :	500.00	--	500.00
		Capital :	347.92	--	347.92
93	Namami Gangey and Rural Water Supply Department	Revenue :	98.00	--	98.00
95	Irrigation Department (Establishment)	Capital :	1.00	--	1.00
Total :		Revenue :	1328922.56	508007.11	1836929.67
		Capital :	612431.00	337.05	612768.05
Grant Total :			1941353.56	508344.16	2449697.72

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under Article 205 *read* with Article 204 of the Constitution, an Appropriation Bill has to be introduced in the State Legislature after demands for Supplementary Grants have been voted by the Legislative Assembly.

This Bill provides for the appropriation out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh of all moneys required to meet the Supplementary Grants made by the Uttar Pradesh Legislative Assembly and the Supplementary Expenditure *charged* on the Consolidated Fund of the State in respect of the financial year 2025-2026.

The Uttar Pradesh Appropriation (Supplementary 2025-2026) Bill, 2025 is introduced accordingly.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 317 राजपत्र-2026-(962)-599 प्रतियां-(डी०टी०पी० / ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 141 सा० विधायी-2026-(963)-300 प्रतियां-(डी०टी०पी० / ऑफसेट)।